माननीय न्यायालय डॉ. सरोजनी सक्सेना, न्यायमूर्ति

नरूला एंटरप्राइजेज,- अपीलकर्ता

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य,-उत्तरदाता

1980 का एफ. ए. ओ. सं. 176

19नवंबर, 1996।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948-धारा 39,40,75 (i) (छ) और 82 (2)-कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950-विनियम 10 (ख)-अंशदान जमा करने की देयता अधिनियम की प्रयोज्यता की तिथि से उत्पन्न होती है-नियोक्ता कटौती और अंशदान करने के लिए वैधानिक दायित्व के अधीन है।- कोड संख्या जारी करने में निगम की देरी पूर्व देयता और पिछली अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को दोषमुक्त नहीं करेगी-यह दलील कि कुछ कर्मचारियों ने सेवा छोड़ दी है, नियोक्ता को योगदान जमा करने से छूट देने का कोई आधार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी-निगम ने 12 अप्रैल, 1978 को आवेदक-अपीलार्थी को एक कोड संख्या आबंटित की थी, लेकिन इस आड़ में अपीलार्थी 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल, 1978 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के अंशदान को जमा करने के अपने दायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है। इस मामले में प्रत्यर्थी-निगम ने 16 अप्रैल, 1978 को एक मांग नोटिस दिया, जिसमें उपरोक्त अवधि के लिए अंशदान जमा करने की मांग की गई। लेकिन मेरे विचार में, मांग सूचना प्राप्त किए बिना भी आवेदक-अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 39 और 40 के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को निगम के पास जमा करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के तहत था। कोड संख्या किसी कारखाने या प्रतिष्ठान को उनके पत्राचार के साथ-साथ दस्तावेजों का पता लगाने की सुविधा के लिए आवंटित की जाती है, लेकिन न तो अधिनियम और न ही विनियमों में यह प्रावधान है कि जब तक कारखाने को कोड संख्या आवंटित नहीं की जाती है, तब तक यह अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा करने के लिए किसी भी वैधानिक दायित्व के तहत नहीं है।

(पैरा 19)

रमेश कुमार, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

फैसला

डॉ. (श्रीमती) सरोजनी सक्सेना, न्यायमूर्ति

(1) आवेदक-अपीलार्थी ने यह अपील कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,

1948 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 (2) के तहत 14 जनवरी, 1990 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 75 (i) (g) के तहत दायर उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

(2) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी ने 1 दिसंबर, 1975 से अपना प्रतिष्ठान चलाना शुरू कर दिया था। चूंकि इस प्रतिष्ठान में 30 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे थे, इसलिए अपीलार्थी ने 15 जनवरी, 1976 को प्रत्यर्थी-निगम को एक कोड संख्या देने के लिए एक पत्र भेजा, ताकि अधिनियम के तहत आवश्यक योगदान निगम के पास जमा किया जा सके। इसके बाद निगम को कई अनुस्मारक भी भेजे गए लेकिन निगम द्वारा 12 अप्रैल, 1978 को आवेदक-अपीलार्थी को कोड नंबर जारी किया गया। 16 अप्रैल, 1978 को, प्रत्यर्थी-निगम ने यह निर्दिष्ट करते हुए मांग नोटिस भेजा कि आवेदक-अपीलार्थी ने 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा नहीं किया है, जो 16,256.75 रुपये आता है। इस मांग सूचना को प्राप्त करने पर अपीलार्थी ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि चूंकि अधिनियम के तहत आवेदक-अपीलार्थी को कोई कोड संख्या आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए यह अपनी ओर से और अपने कर्मचारियों की ओर से अंशदान जमा/भुगतान करने के लिए किसी वैधानिक दायित्व के तहत नहीं था। आवेदक-अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 75 (1) (जी) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि मांग नोटिस को माफ कर दिया जाए क्योंकि कोड संख्या के आवंटन के बाद, आवेदक-अपीलार्थी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से अंशदान जमा/भुगतान कर रहा है। इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि निगम पिछली तारीख से अंशदान के बकाया की मांग नहीं कर सकता है।

(3) प्रत्यर्थी-निगम ने अपना जवाब दाखिल किया और विभिन्न आधारों पर याचिका का विरोध किया, जो इस अपील के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसने स्वीकार किया कि कोड नंबर आवेदक-अपीलार्थी को 12 अप्रैल, 1978 को आवंटित किया गया था, लेकिन यह दलील दी गई थी कि चूंकि आवेदक ने निगम को हदबस्त नंबर प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए कोड नंबर आवेदक-अपीलार्थी को आवंटित नहीं किया गया था। इस बात से भी इनकार किया गया कि निगम पिछली तारीख से अंशदान के बकाया की मांग नहीं उठा सकता है।

(4) तदनुसार मुद्दे तैयार किए गए और पक्षों ने अपने गवाहों से पूछताछ की।

(5) बीमा न्यायालय ने साक्ष्य की जांच की और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आवेदक-अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-निगम को हदबस्त संख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए निगम आवेदक-अपीलार्थी को कोड संख्या आवंटित नहीं कर सकता था। चूंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक 1 दिसंबर, 1975 से 30 कर्मचारियों के साथ अपना प्रतिष्ठान चला रहा था, इसलिए इसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था क्योंकि आवेदक-अपीलार्थी ने स्वयं 15 जनवरी, 1976 को निगम को एक कोड संख्या आवंटित करने के लिए एक पत्र भेजा था। इसलिए निगम को न केवल नियोक्ता की ओर से बल्कि 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक कर्मचारियों की ओर से भी अंशदान का दावा करने का वैधानिक अधिकार था, जो आवेदक-अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं किए गए थे। अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निगम उपर्युक्त अवधि के लिए अंशदान के इन बकाया का दावा करने का हकदार था। इस प्रकार याचिका को खारिज कर दिया गया।

(6) आवेदक-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 (संक्षेप में विनियम) के विनियम 10-ख को ध्यान में रखते हुए जैसे ही कोई कारखाना या प्रतिष्ठान उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को नियोक्ता का पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करता है, उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय उसे एक नियोक्ता कोड संख्या आवंटित करेगा और उस संख्या के नियोक्ता को सूचित करेगा। यदि यह कोड संख्या नियोक्ता को आवंटित की जाती है, तो नियोक्ता को अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के अनुसार और उपयुक्त कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में उसके द्वारा तैयार या पूरा किए गए सभी दस्तावेजों पर यह कोड संख्या दर्ज करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने तर्क दिया कि 15 जनवरी, 1976 को आवेदक-अपीलार्थी ने प्रतिवादी-निगम को आवेदक-अपीलार्थी को एक कोड संख्या आवंटित करने के लिए एक पत्र भेजा। इसके बाद विभिन्न अनुस्मारक भेजने के बावजूद, प्रतिवादी-निगम अप्रैल, 12,1978 तक आवेदक को कोड संख्या आवंटित करने में विफल रहा। अतः 12 अप्रैल, 1978 तक अपीलार्थी प्रत्यर्थी-निगम के पास अधिनियम के अधीन अंशदान जमा करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए, उसके गवाह ने शपथ पर स्वीकार किया है कि शुरू में कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर्मचारियों के योगदान के रूप में की

गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि कोड नंबर आवेदक-अपीलार्थी को आवंटित नहीं किया गया था और इसलिए आवेदक नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ प्रतिवादी-निगम के साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा करने की स्थिति में नहीं था।

(7) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कोड संख्या के आवंटन के चार दिनों के तुरंत बाद प्रत्यर्थी-निगम ने 16 अप्रैल, 1978 को एक मांग सूचना भेजी, जिसमें 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान का दावा किया गया था। के. आर. सुब्बायर बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उपरोक्त पिछली अवधि के लिए अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा करने की मांग करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

(8) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उस अवधि के दौरान चूंकि आवेदक-अपीलार्थी को कोई कोड संख्या आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए इसने कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से नहीं घटाया। जो कर्मचारी उस अवधि के दौरान उनके साथ काम कर रहे थे, वे अब आवेदक-अपीलार्थी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, अब आवेदक-अपीलकर्ता उन कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारियों के योगदान की कटौती नहीं कर सकता है जो पहले ही अपना रोजगार छोड़ चुके हैं।

(9) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोड संख्या 12 अप्रैल, 1978 को आवेदक-अपीलार्थी को आवंटित की गई थी, लेकिन पहले दिन से ही जब आवेदक-अपीलार्थी ने अपना व्यवसाय शुरू किया और 15 जनवरी, 1976 को निगम को एक नोटिस दिया, यह स्वीकार करते हुए कि अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होते हैं, यह एक वैधानिक कर्तव्य के तहत था कि कर्मचारियों के अंशदान की कटौती की जाए और नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ प्रत्यर्थी निगम के साथ कर्मचारियों के अंशदान को जमा किया जाए। जमा बैंक में किया जाना था, जो कोड संख्या के आवंटन के बिना भी किया जा सकता था। चूंकि आवेदक-अपीलार्थी ने 15 जनवरी, 1976 को कोड संख्या के आवंटन की मांग करते हुए एक पत्र भेजा था और उसके बाद निगम को अनुस्मारक भी भेज रहा था, आवेदक-अपीलार्थी निगम को यह भी सूचित कर सकता था कि उसने नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को बैंक में जमा कर दिया है, जिसका भुगतान निगम को किया जाना है। चूंकि यह अपने

वैधानिक कर्तव्य में विफल रहा, इसलिए निगम 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक की अवधि के लिए इन अंशदानों की मांग करने का हकदार था।

(10) इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनियमों के विनियम 10-बी के तहत प्रत्येक कारखाना या प्रतिष्ठान अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के बाद उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को नियोक्ता का पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इसके खंड (घ) के तहत इस प्रपत्र को प्राप्त करने पर उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय से कारखाने या प्रतिष्ठान को एक नियोक्ता कोड संख्या आवंटित करने की अपेक्षा की जाती है, जिसका उल्लेख सभी पत्राचार और दस्तावेजों आदि पर किया जाना आवश्यक है। कारखाना/प्रतिष्ठान द्वारा। उक्त विनियमों के विनियम 11 में यह भी कहा गया है कि किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रत्येक ऐसे नियोक्ता को उसमें काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से एक घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद नियोक्ता को उन घोषणा पत्रों को निगम के उपयुक्त कार्यालय में भेजने की आवश्यकता होती है। इस तरह के घोषणा पत्र प्राप्त करने पर निगम के उपयुक्त कार्यालय को प्रत्येक को बीमा संख्या आवंटित करने की आवश्यकता होती है! वह व्यक्ति जिसके संबंध में उसे घोषणा पत्र प्राप्त हो गया है। उपयुक्त कार्यालय से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में बीमा संख्या आवंटित की गई है, को प्रपत्र 4 में तैयार पहचान पत्र जारी करे और ऐसे सभी पहचान पत्र नियोक्ता को भेजे। विनियमन 17-ए में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बीमित व्यक्ति को अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, तो नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रपत्र में रोजगार प्रमाण पत्र जारी करेगा जो निदेशक-जनरल द्वारा मांग पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि कोई बीमित व्यक्ति पहचान पत्र की प्राप्ति से पहले अपना अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र खो देता है तो ऐसा प्रमाण पत्र मांग पर भी जारी किया जाएगा।

(11) अधिनियम की धारा 39 और 40 के तहत, प्राथमिक दायित्व न केवल नियोक्ता के योगदान बल्कि कर्मचारियों के योगदान का भुगतान करने के लिए प्रतिष्ठान/कारखाने का है। इन वैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 26 के तहत बनाए गए सामान्य कोष से, कर्मचारी बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, चोट, चिकित्सा उपचार और बीमित व्यक्तियों की उपस्थिति जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए, यह सामाजिक कानून का एक लाभकारी हिस्सा है।

(12) इस अपील में विवाद का वास्तविक बिंदु यह है कि क्या नियोक्ता कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से काटने और नियोक्ता और कर्मचारियों के योगदान को निगम को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि कारखाने/प्रतिष्ठान को संख्या आवंटित नहीं की जाती है? एक अन्य सहायक प्रश्न यह है कि क्या निगम के अधिकारी पिछली अवधि की मांग उठाने के हकदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि के. आर. सुब्बैयर के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अधिनियम और योजना के संपूर्ण प्रावधानों के उचित परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई संदेह नहीं है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने याचिकाकर्ता को 1952 से 1957 तक अतीत की मांग करने के लिए बुलाने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।" उस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का एक विद्वान एकल न्यायाधीश कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजना की व्याख्या कर रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता की स्थापना या उपक्रम 1952 और 1957 के बीच अनदेखे रहे। याचिकाकर्ता ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि अधिनियम उसके व्यवसाय या प्रतिष्ठान पर लागू था, और नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, अधिनियम के आवेदन का विरोध किया। इस आधार पर भी यह निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में कारबार शुरू होने के 15 दिनों के भीतर, आवेदक-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-निगम को 15 जनवरी, 1976 को यह स्वीकार करते हुए एक पत्र भेजा कि यह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और इसलिए इसे एक कोड संख्या आवंटित की जाए। के. आर. सुब्बैयर के मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने उस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि इन प्रावधानों का सार ऐसा है कि उन्हें केवल उस समय से लागू किया जाए जब अधिकारी यह मानते हैं कि कोई विशेष इकाई अधिनियम के दायरे में है और अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना के संदर्भ में परिणामी मांग करते हैं।

(13) विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तर्क पर विचार किया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम समामेलन रेपको लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रबंधन अधिनियम की धारा 39 के तहत अपनी मर्जी से योगदान करने के लिए उत्तरदायी है और इस तरह का भुगतान निगम द्वारा किसी भी मांग पर सशर्त नहीं किया जाता है।

(14) कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम टी. सी. वर्मानी, न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल, (जैसा कि वे तब थे) ने भी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों पर विचार किया और कहा कि "अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निगम को कारखाने के मालिकों को सूचित करते रहने का कर्तव्य देता है कि वे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। निगम नियोक्ता का सलाहकार नहीं है और वास्तव में, अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए जाने के क्षण में कारखाने के प्रमुख नियोक्ता पर एक कर्तव्य लगाया गया है और उस मामले के लिए कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से काटकर नियोक्ता के योगदान के साथ निगम को भेजना है। यदि नियोक्ता कर्मचारी के अंशदान की कटौती करने में विफल रहता है, तो निगम के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है क्योंकि अधिनियम की धारा 40 में अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता पर डाल दी गई है। इस प्रकार योगदान नियोक्ता द्वारा उस तारीख से किया जाना है जिस दिन कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है न कि निगम से मांग की तारीख से।

(15) क्षेत्रीय निदेशक ईएसआई निगम बनाम फैशन फैब्रिक्स मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों पर भी विचार किया और कहा कि यह परिस्थिति कि निगम द्वारा उचित समय पर यह पता नहीं चला था कि प्रतिष्ठान अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, नियोक्ता को योगदान देने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

(16) बॉम्बे अमोनिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 39,45-बी और 37-डी के प्रावधानों पर विचार किया और कहा कि यह नियोक्ता पर बाध्यकारी है कि वह अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अंशदान का भुगतान स्वयं करे और उनका दायित्व इस तथ्य पर निर्भर नहीं करेगा कि उन्होंने इस राशि को कर्मचारियों से वसूल किया था या नहीं। यह अधिक होगा, नोटिस दिए जाने के बाद कि वे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के प्रति समर्पण करने के लिए कहा जाता है। यदि, इसके बावजूद, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की है, तो उन्हें खुद को दोषी ठहराना होगा और विभाग के कारण उनकी देनदारी प्रभावित नहीं होगी।

(17) आगे यह देखा गया है कि "अधिनियम की धारा 39 में अंशदान को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा देय अंशदान को कवर करने के रूप में परिभाषित किया गया है, और उप-धारा के तहत अंशदान प्रत्येक सप्ताह के अंत तक देय है। नियोक्ता के दायित्व को धारा 40 द्वारा संदेह से परे स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पहली बार में अंशदान के लिए मूल दायित्व नियोक्ता का होगा, जिसका निहितार्थ यह होगा कि क्या कर्मचारी ने अपना अंशदान किया है या नहीं, और क्या नियोक्ता ने कर्मचारी को वह अंशदान करने के लिए बुलाया था या नहीं; जहां तक अधिनियम के तहत प्राधिकरणों का संबंध है; मुख्य नियोक्ता पूरे अंशदान के लिए उत्तरदायी है, एक बार यह दिखाया जाता है कि अधिनियम उस नियोक्ता पर लागू होता है।

(18) कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम होटल कल्पक इंटरनेशनल में, सर्वोच्च न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार किया कि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान को 11 अक्टूबर, 1985 से 31 मार्च, 1988 तक अधिनियम की धारा 40 के तहत अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, क्योंकि प्रतिष्ठान 31 मार्च, 1988 को बंद था। विचार के लिए मुख्य बिंदु यह था कि क्या योगदान की मांग को बंद व्यवसाय के खिलाफ लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः—

“उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि उनके कार्य प्रारंभ होने की तिथि, अर्थात् 11 जुलाई, 1985 से योगदान करने का दायित्व था। यह पहले से ही धारा 40 के तहत देखा गया है, प्राथमिक दायित्व उसका है, न केवल नियोक्ता के योगदान का भुगतान करना बल्कि कर्मचारियों के योगदान का भी भुगतान करना। इसलिए, उन्हें यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि चूंकि उन्होंने कर्मचारियों के वेतन पर कर्मचारियों के योगदान की कटौती नहीं की थी, इसलिए उन्हें इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था। यदि ऐसे विवाद को स्वीकार किया जाना है तो धारा 40 की उप-धारा को सौंपने का उद्देश्य पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। आखिरकार जब वह कर्मचारियों का योगदान देता है तो वह मजदूरी से कटौती करने का हकदार होता है। इससे पहले, वैधानिक प्रावधानों के लागू होने के बल पर, इस प्रासंगिक अवधि, अर्थात् 11 जुलाई, 1985 से 31 मार्च, 1988 के दौरान योगदान करने का दायित्व उत्पन्न हुआ। इसमें कोई फायदा नहीं है "।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि "यह निष्कर्ष निकालना भी उतना ही गलत है कि क्योंकि कर्मचारी चले गए थे, इसलिए दोषारोपण करने का कोई दायित्व नहीं है। यह ध्यान से याद रखना होगा कि योगदान करने का दायित्व प्रतिष्ठान के शुरू होने की तारीख से उत्पन्न हुआ है और बंद होने तक एक निरंतर

दायित्व है। सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए धारा 26 के तहत एक सामान्य निधि स्थापित करने के उद्देश्य को फिर से विफल कर दिया जाएगा यदि इस तरह का निर्माण किया जाता है।

(19) इस प्रकार, मेरे सुविचारित विचार में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी-निगम ने 12 अप्रैल, 1978 को आवेदक-अपीलार्थी को एक. कोड संख्या आवंटित की थी, लेकिन इसकी आड़ में आवेदक-अपीलार्थी 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के अंशदान को जमा करने के अपने दायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है। इस मामले में प्रत्यर्थी-निगम ने 16 अप्रैल, 1978 को एक मांग नोटिस दिया, जिसमें उपरोक्त अवधि के लिए अंशदान जमा करने की मांग की गई। लेकिन मेरे विचार में, मांग सूचना प्राप्त किए बिना भी आवेदक-अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 39 और 40 के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के अंशदान को निगम के पास जमा करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के तहत था। किसी कारखाने या प्रतिष्ठान को उनके पत्राचार के साथ-साथ दस्तावेजों का पता लगाने के लिए कोड संख्या आवंटित की जाती है, लेकिन न तो अधिनियम और न ही विनियमों में यह प्रावधान है कि जब तक कारखाने को कोड संख्या आवंटित नहीं की जाती है, तब तक यह अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा करने के लिए किसी भी वैधानिक दायित्व के तहत नहीं है।

(20) यहां तक कि तर्क के लिए भी यदि यह देखा जाए कि जब तक आवेदक-अपीलार्थी को दिनांक 16 अप्रैल, 1978 की मांग सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसने अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के अंशदान को जमा नहीं किया है, तब तक उस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है, मांग सूचना प्राप्त करने के तुरंत बाद 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल, 1978 तक इन अंशदानों को जमा नहीं करके उसने उस दायित्व को सकारात्मक रूप से वहन किया है। यदि पहले, जैसा कि उसके गवाह ने स्वीकार किया है, आवेदक-अपीलार्थी कर्मचारियों के अंशदान को उनके वेतन से काट रहा था, जो कि बंद कर दिया गया था, तो मांग सूचना प्राप्त करने के तुरंत बाद अपीलार्थी को 1 दिसंबर, 1975 से अधिनियम के तहत इन अंशदानों को जमा करना चाहिए था, जिस दिन उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था। चूंकि मांग नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, यह अधिनियम के तहत इन अंशदानों को जमा करने में विफल रहा है और आगे अधिनियम की धारा 75 के तहत याचिका दायर की है, 1 दिसंबर, 1975 से अप्रैल 1978 तक इन अंशदानों का भुगतान करने के अपने दायित्व पर विवाद करते हुए, यह जहां

तक ब्याज के भुगतान का संबंध है, न्यायालय से विवेकाधीन राहत नहीं ले सकता है। अधिनियम के साथ-साथ विनियमों के तहत यदि नियोक्ता वैधानिक समय के भीतर अधिनियम के तहत नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के योगदान को जमा करने में विफल रहता है, तो वह ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए निगम 16,256.75 रुपये की राशि पर भी ब्याज की मांग कर रहा है, जो कि उक्त अवधि के लिए अधिनियम के तहत अंशदान की राशि है।

(21) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अब तक अधिकांश कर्मचारी जो दिसंबर 1975 से अप्रैल 1978 की अवधि के दौरान आवेदक-अपीलार्थी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपना रोजगार छोड़ दिया है और चूंकि उस अवधि के दौरान इसने कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से नहीं घटाया है, इसलिए अब वे अंशदान निगम में जमा करने में असहाय है।

(22) यह तर्क भी गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम सामाजिक विधान का एक भाग है और कर्मचारियों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया है। यदि इस तरह की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह योजना को बढ़ावा नहीं देगा और ऐसे नियोक्ताओं द्वारा प्रासंगिक समय पर और कुछ वर्षों के बाद कर्मचारियों के योगदान को जमा नहीं करने के लिए एक उपयोगी लीवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यह कहने के लिए कि अब चूंकि उन कर्मचारियों ने अपना रोजगार छोड़ दिया है, इसलिए इसे अवधि के लिए उनके योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अधिनियम के प्रावधानों को नकारात्मक बना देगा।

(23) तदनुसार, इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा